



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 04

पटना, बुधवार,

2 माघ 1946 (श0)

22 जनवरी 2025 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-17
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	18-18
पूरक	---
पूरक-क	19-20

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

उद्योग विभाग

अधिसूचना

14 जनवरी 2025

सं0 06(स0) विविध (रसायन निगम)-22/2019-201--श्री विनय कुमार मल्लिक, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उनके स्थान पर सुश्री निशा कुमारी, सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को आर्टिकल्स ऑफ एसोशिएसन के प्रावधानों के तहत बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 एवं बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि0 पटना के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में अगले आदेश तक नामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

7 जनवरी 2025

सं0 02स्था0-11/2024-051/वि0स01--सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-3528, दिनांक-31.12.2024 के आलोक में वरीय प्रतिवेदक के पद पर सविदा के आधार पर नियोजित श्री मधुप कुमार का दिनांक-01.01.2025 के पूर्वां में योगदान स्वीकार किया जाता है।

आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

3 जनवरी 2025

सं0 02स्था0-277/2017-022/वि0स01--सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-3530, दिनांक-31.12.2024 के आलोक में निदेशक के पद पर सविदा के आधार पर नियोजित श्री असीम कुमार का दिनांक-01.01.2025 के पूर्वां में योगदान स्वीकार किया जाता है।

आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

20 दिसम्बर 2024

सं0 02स्था0-169/2018-3486/वि0स01--श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर-11 में प्रतिमाह अंके-80,900/- रुपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियमावली, 1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कड़िका-G के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 में एल०टी०सी० सुविधा के तहत दिनांक-26.12.2024 से 31.12.2024 तक देश के अन्दर पटना से बवाना (नई दिल्ली) एवं बवाना (नई दिल्ली) से पटना वापसी की यात्रा के निमित्त दिनांक-26.12.2024, 27.12.2024, 30.12.2024 एवं 31.12.2024 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक- 28.12.2024 एवं 29.12.2024 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक-26.12.2024 से 31.12.2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

17 दिसम्बर 2024

सं० 2स्था०-267/2017-3418/वि०स०।-श्री संजय कुमार, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, जो वतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-86,100/- रुपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियमावली, 1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कड़िका G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 में एल०टी०सी० सुविधा के तहत दिनांक- 19.12.2024 से 30.12.2024 तक देश के अन्दर पटना से बंगलुरु (कर्नाटक) एवं बंगलुरु (कर्नाटक) से पटना वापसी की यात्रा के निमित्त दिनांक-19.12.2024, 20.12.2024, 23.12.2024, 26.12.2024, 27.12.2024 एवं 30.12.2024 को आकस्मिक अवकाश, दिनांक-24.12.2024 को प्रतिबंधित अवकाश तथा दिनांक-21.12.2024, 22.12.2024, 28.12.2024 एवं 29.12.2024 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक-19.12.2024 से 30.12.2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

13 अगस्त 2024

सं० 497/स्था०—अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक-918, दिनांक-11.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मो० शाहनवाज अली शाह, कार्यालय परिचारी दिनांक-22.02.2013 से बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित हैं। पुनः अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक-1327, दिनांक-24.08.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मो० शाह से स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा उनके घर के पता पर पत्र तामिला हेतु भेजा गया, परन्तु सपरिवार घर पर अनुपस्थित पाये गये। तत्पश्चात निबंधित डाक से भी उनके घर के पता पर पत्र भेजा गया, वह पत्र भी बिना तामिला के वापस आ गया।

अस्तु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(i)(क) के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-10-11/2013-1812/स्था०, दिनांक-18.12.2014 द्वारा मो० शाहनवाज अली शाह, कार्यालय परिचारी, अंचल कार्यालय, सदर दरभंगा को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया एवं अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा को इस कार्यालय के पत्रांक-10-11/2013-2006/स्था०, दिनांक-19.09.2013 एवं विभिन्न स्मार पत्रों के द्वारा मो० शाह, कार्यालय परिचारी के विरुद्ध आरोप प्रपत्र-‘क’ गठित कर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के माध्यम से भेजने हेतु निदेश दिया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक-996, दिनांक-02.05.2023 के द्वारा मो० शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र-‘क’ अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। उक्त आरोप प्रपत्र-‘क’ को अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 640/स्था०, दिनांक-01.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु प्रभारी अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा के पत्रांक-244/वि०जाँ०, दिनांक-04.11.2023 द्वारा मो० शाहनवाज अली शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो निम्नवत है:-

क्र०	आरोप प्रपत्र “क” में लगाये गये अवचार या कदाचार का लांछनो का सार	आरोपी कर्मी का जवाब	उपस्थापन पदाधिकारी का जवाब	जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन
1	2	3	4	5
1	1. मो० शाहनवाज अली शाह कार्यालय परिचारी बिना सूचना के दिनांक 22.02.2013 से अपने कर्तव्य एवं	निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मैं मो० शाहनवाज अली शाह, पिता- स्व० अब्दुल जब्बार निवासी ग्राम- पुरखोपट्टी, पोस्ट- लहेरियासराय थाना- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा	उपर्युक्त विषयक संबंध में प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न मो० शाहनवाज अली शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी, सदर दरभंगा द्वारा अपने बचाव पक्ष में दिये गए आवेदन एवं संलग्न कागजात	उपस्थापन पदाधिकारी के जवाब से स्पष्ट है कि मो० शाहनवाज अली शाह, कार्यालय परिचारी बिना सूचना के दिनांक 22.02.2013 से अपने कर्तव्य एवं कार्यालय से लगातार अनुपस्थित है। इनके द्वारा

<p>कार्यालय से लगातार अनुपस्थित है।</p>	<p>का रहने वाला हूँ। मेरी नियुक्ति दिनांक— 29.04.2006 को अनुकम्पा के आधार पर अंचल कार्यालय सदर दरभंगा में कार्यालय परिचारी के पद पर हुई थी। नियुक्ति होने के बाद मैं निष्ठा पूर्वक कार्यालय का काम काज करने लगा। अचानक मेरी मानसिक स्थिति एकाएक दिनांक— 22.02.2013 को अत्यधिक दयनीय हो जाने के कारण कार्यालय जाने से असमर्थ हो गया। यहाँ तक कि मैं अपने आप का आपा खो चुका था, जिससे मुझे किसी भी प्रकार की बातों का अनसुनी महसूस होने लगा। जिसका ईलाज एवं झारफुक भी स्थानीय तांत्रिक के यहाँ भी कराया गया। इसी दरमियान मेरी पत्नी का भी मेरा मानसिक स्थिति देखकर तबियत बिगड़ने लगा जिसका ईलाज लगातार जनकल्याण डायग्नोस्टिक सेंटर कुमुदनी झा के यहाँ कराया गया। इसके बाद हम दोनों पति एवं पत्नी का इलाज लगातार होता रहा जिस ईलाज का प्रिंसकेप्सन का छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न किया जाता है। विदित हो कि मैं अपना मानसिक इलाज कराकर पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ, इसलिए मैंने पुनः अंचल कार्यालय में कार्यालय परिचारी के पद पर योगदान दे रहा हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसी कोई गलती नहीं किया हूँ और न ही किसी अन्य जगह किसी लाभ के पद पर कार्यरत था। जिसका जाँच विभागीय ईकाई से कराया जा सकता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त लिखित जवाब को बिन्दुवार जाँच करते हुए मुझे पुनः</p>	<p>के सम्बन्ध में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ निम्न प्रकार है:—</p> <p>1. यह कि मो० शाहनवाज अली शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी, सदर दरभंगा दिनांक 22.02.2013 से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 314 दिनांक 15.03.2013 द्वारा स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा को दी गयी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 918 दिनांक 11.05.2013 के द्वारा बिना किसी सूचना के अनुपस्थिति की सूचना स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा को दी गयी, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि, ऐसा ज्ञात होता है कि मो० शाहनवाज अली शाह किसी हत्या के मामले में आरोपित है। (छायाप्रति संलग्न)</p> <p>2. अपने आवेदन में मो० शाह का कहना है कि दिनांक 22.02.2013 को अचानक मानसिक स्थिति खराब हो गयी, जिससे कार्यालय आने में असमर्थ हो गए, बिल्कुल गलत एवं गुमराह करने वाला है। सच्चाई यह है कि दिनांक 22.02.2013 को इनके द्वारा अन्य परिजनों सहित राम दाई देवी, पति—स्व० योगेन्द्र राम, सा० पुरखोपट्टी जो इनके पड़ोसी हैं के साथ मारपीट की गयी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिसकी प्राथमिकी राम दाई देवी द्वारा स्थानीय बहादुरपुर थाना में दर्ज कराया गया। (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न है) और उसी दिन से ये घर छोड़कर फरार हो गए। बाद में अनौपचारिक सूचना मिली कि घायल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में स्थानीय थाना से केस डायरी की मांग की जा</p>	<p>अपने अनुपस्थिति अवधि में मानसिक स्थिति खराब होने का जिक्र किया गया है। लेकिन किसी मानसिक अस्पताल का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ये बहादुरपुर थाना काण्ड संख्या —75/13 दिनांक 22.02.2013 में आरोपित होने के कारण फरार थे। अतः इस संबंध में लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है।</p>
---	--	--	--

	<p>कार्यालय परिचारी के पद पर योगदान देने का आदेश दिया जाय। इसके लिए आवेदक श्रीमान् का आभारी रहेंगा।</p>	<p>सकती है, जिससे यह और भी स्पष्ट हो सकेगा कि ये इसी कारण घर और अपने कर्तव्य से फरार हो गए।</p> <p>3. इनका यह भी कहना कि इनके द्वारा अपना आपा खो दिया गया, यह सही है, कारण कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ये सपरिवार घर छोड़कर चले गए थे क्योंकि इस कार्यालय के पत्रांक 1080, दिनांक- 26.06.2013 एवं पत्रांक-1115, दिनांक- 08.07.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसे रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया, परन्तु इनके घर पर परिवार के किसी सदस्य के नहीं रहने के कारण वापस आ गया। विशेष दूत द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया कि इनके घर पर ताला लगा है। (छायाप्रति संलग्न है।)</p> <p>4. अपने आवेदन के साथ इनके द्वारा संलग्न चिकित्सा पुर्जा बनावटी है, क्योंकि उक्त पुर्जा में अंकित तिथि में छेड़छाड़कर वर्ष बनाया गया है। संलग्न पुर्जा किसी मो० तबरेज का है, जिसे बाद में मो० शाहनवाज अली शाह उसपे ऊपर में जोड़ा गया है। अंकित तिथि 28.12.2022 में छेड़-छाड़ कर 2013 बनाया गया है, जो अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जाता है। दूसरा चिकित्सा पुर्जा (Dr. S. K. Jha) भी मो० तबरेज शाह का है जो 09.12.2022 का है, उसमे भी बाद में अलग लिखावट से मो० शाहनवाज अली शाह लिखा गया है। तीसरा पुर्जा जो सिटी हॉस्पिटल का है, वह भी मो० तबरेज शाह का है, जो डिस्चार्ज पुर्जा है, में भी मो० शाहनवाज अली शाह ऊपर में लिखा गया है। तीनों चिकित्सा पुर्जा के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तीनों पुर्जा पर मो०</p>
--	---	---

			<p>शाहनवाज अली शाह एक ही लिखावट में लिखा गया है, जबकि तीनो चिकित्सा पुर्जा अलग अलग डाक्टर का है।</p> <p>5. मो० शाह का अपने आवेदन में यह कहना कि इसी बीच में इनकी पत्नी का भी इलाज चल रहा था, यह भी गलत है। आवेदन के साथ संलग्न इनके पत्नी शमा खातून का चिकित्सा पुर्जा भी 2019 एवं 2020 का है, जिसमें आवेदक शाहनवाज अली शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी के कर्तव्य से अनुपस्थिति का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार मो० शाहनवाज अली शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी द्वारा संलग्न चिकित्सा पुर्जा बनावटी प्रतीत होता है।</p> <p>6. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शाहनवाज अली शाह दिनांक-22.02.2013 को प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत ही घर छोड़कर फरार हुए एवं दिनांक 22.02.2013 से लगातार अब तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे हैं।</p>	
2	<p>मो० शाहनवाज अली शाह से इस कार्यालय के पत्रांक- 1080, दिनांक 26.06.2013 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के पश्चात पत्रांक-1115, दिनांक-08.07.2013 निबंधित डाक से पत्र भेजा गया, जो बेगैर तामिला के वापस आ गया है।</p>		<p>7. यह कि बिहार सेवा संहिता के नियम-76 में भी यह स्पष्ट है कि जब तक कि किसी मामले की खास परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार अन्यथा निर्धारित न करे, सरकारी सेवक, भारत में बाह्य सेवा को छोड़कर अन्यत्र छुट्टी की अवधि के साथ या बिना छुट्टी के कर्तव्य से पांच वर्ष तक लगातार अनुपस्थिति के बाद, सरकारी-नियोजन में नहीं रह जाता है। मो० शाह द्वारा समर्पित चिकित्सा पुर्जा एवं अन्य कागजात से स्पष्ट है कि मो० शाह 22.02.2013 से लगातार अब तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे हैं। इनके द्वारा संलग्न योगदान आवेदन निबंधित डाक से</p>	<p>उपस्थापन पदाधिकारी के जबाब एवं संलग्न प्राथमिकी के प्रति से स्पष्ट है कि ये बहादुरपुर थाना काण्ड संख्या- 75/13 दिनांक 22.02.2013 में हत्या के मामले में आरोपित होने के कारण फरार थे, तथा इनके घर पर भी कोई उपलब्ध नहीं था। अतः इस संबंध में लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है।</p>

			भेजने का दावा किया गया है। विदित हो कि किसी भी कर्म का योगदान निबंधित डाक से भेजने का प्रावधान नहीं है और न ही अंचल कार्यालय में इनका योगदान स्वीकृत किया गया है।	
3	ये लगातार लगभग 10 (दस) वर्षों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं।		मो0 शाह बिना किसी छुट्टी के ही लगातार अब तक लगभग 10 वर्षों से ज्यादा से अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में ये किसी भी प्रकार के अनुतोष के हकदार नहीं है। इन पर बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।	बिहार सेवा संहिता के नियम-76 में यह स्पष्ट है कि जब तक कि किसी मामले की खास परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार अन्यथा निर्धारित न करे, सरकारी सेवक, भारत में बाह्य सेवा को छोड़कर अन्यत्र छुट्टी की अवधि के साथ या बिना छुट्टी के कर्तव्य से पांच वर्ष तक लगातार अनुपस्थिति के बाद, सरकारी-नियोजन में नहीं रह जाता है। उपस्थापन पदाधिकारी के अनुसार मो0 शाह द्वारा समर्पित चिकित्सा पुर्जा एवं अन्य कागजात से स्पष्ट है कि मो0 शाह दिनांक-22.02.2013 से लगातार अब तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे हैं।

मो0 शाहनवाज अली शाह, कार्यालय परिचारी, सदर दरभंगा दिनांक 22.02.2013 से बहादुरपुर थाना काण्ड संख्या-75/13, दिनांक 22.02.2013 में हत्या के मामले में आरोपित होने के कारण फरार थे, और कार्यालय से लगातार अनुपस्थित थे। अतः इनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम-76 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रपत्र- 'क' के क्रमांक-01 एवं 02 पर अंकित आरोप प्रमाणित पाया गया है तथा क्रमांक-03 में आरोप की पुष्टि की गई है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक-07/मु0/स्था0, दिनांक-14.03.2024 द्वारा संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए मो0 शाहनवाज अली शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी, अंचल कार्यालय, सदर दरभंगा से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई।

मो0 शाहनवाज अली शाह द्वारा दिनांक-01.04.2024 को अपना द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया, जो निम्नवत है :-

“मेरे विरुद्ध अंचल कार्यालय, सदर दरभंगा में कार्यालय परिचारी के पद पर पदस्थापन अवधि में दिनांक-22.02.2013 से अपने कर्तव्य एवं कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए भवदीय आदेश ज्ञापांक-640/स्था0, दिनांक-01.06.2023 के माध्यम से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें मेरे द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, परन्तु संचालन पदाधिकारी के द्वारा इस पर कोई संज्ञान लिये बिना ही उपस्थापन पदाधिकारी के भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम-76 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई, जो भवदीय के अधिकारिता में हस्तक्षेप प्रतीत होता है। प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में भवदीय को निम्नवत अपित करना है :-

1. कि मेरी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर कार्यालय परिचारी के पद पर दिनांक-29.04.2006 को हुई थी। नियुक्ति के उपरान्त आरोप प्रतिवेदन की तिथि तक मेरे द्वारा नियमित रूप से अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जाता रहा है।

2. कि दिनांक-22.02.2013 को मेरा तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस कारण परिजनों द्वारा समुचित ईलाज हेतु बाहर ले गये, परन्तु इसी क्रम में स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर मैं धीरे-धीरे अवसाद से ग्रसित हो गया, जिस कारण मैं गैर व्यवहारिक बातें एवं व्यवहार आदि करने लगा, जिससे परिजन भी परेशान रहने लगे।

3. कि मेरे चिकित्सा अवधि में मेरी पत्नी के द्वारा वर्णित तथ्यों के आलोक में एक अभ्यावेदन तत्कालीन अंचल अधिकारी महोदय, सदर को जुलाई 2013 में दिया गया था, जिसमें याचना की गई थी कि मेरे पति के पूर्ण स्वस्थ होने के उपरान्त कार्यालय में योगदान समर्पित किया जायेगा।

4. कि स्वस्थ होने के उपरान्त मैंने माह दिसम्बर-2017 में कार्यालय में योगदान समर्पित किया, परन्तु कार्यालय द्वारा टालमटोल करते हुए न तो मेरे योगदान को स्वीकृत किया गया और न ही उपस्थिति पंजी पर मेरा नाम अंकित किया गया, जिस कारण मैं हाजिरी बनाने से वंचित रहा। इसके बावजूद भी मैं निरंतर कार्यालय जाता रहा तथा समय-समय पर तत्कालीन अंचलाधिकारी महोदय से भी मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराता रहा, तो उनके द्वारा आश्वस्त किया जाता रहा है कि हाजिरी बन जायेगी, घबराने की कोई बात नहीं है। अंचलाधिकारी महोदय के आश्वासन पर मैं बिना हाजिरी के ही अपना कार्य करता रहा, परन्तु समय-समय पर हाजिरी के संदर्भ में प्रधान सहायक से मतभेद भी हो जाता था।

5. कि मेरे कार्यालय में उपस्थित रहने के क्रम में ही कार्यालय द्वारा चुपचाप तरीके से मेरे विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर भवदीय कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया।

6. कि मेरे विरुद्ध आरोप पत्र गठित होने की जानकारी कुछ दिनों के उपरान्त जिला से ही प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा तत्कालीन अंचलाधिकारी महोदय से पृच्छा किया तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई बात नहीं है, जिला से इसपर जवाब आ जाएगा तो हाजिरी भी बन जाएगी एवं वेतनादि का भी भुगतान हो जाएगा।

7. कि भ्रामक तथ्यों के आधार पर आरोप पत्र के गठित हो जाने के उपरान्त मैं पुनः अवसाद में जाने लगा, जिस कारण मुझे पुनः अपना ईलाज कराना पड़ा तथा इसी क्रम में कोविड-19 के संदर्भ में प्रोटोकॉल आदि निर्गत हो जाने के कारण मैं अंचलाधिकारी महोदय से इस संबंध में कोई पृच्छा नहीं किया और न ही वेतनादि के संबंध में कोई अनुरोध किया।

8. कि कोविड-19 प्रकोप के कम होने के उपरान्त कार्यालय के ही एक कर्मी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा समर्पित योगदान को फाड़कर फेंक दिया गया है, तदोपरान्त मेरे द्वारा पुनः एक योगदान तत्कालीन अंचलाधिकारी महोदय को दिया गया, जिसे उनके द्वारा स्वयं अपने डायरी में रख लिया गया तथा बताया गया कि काम करते रहो, जिला से मंतव्य प्राप्त होने के उपरान्त हाजिरी बनवाकर वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।

9. कि मेरे द्वारा दुबारा योगदान समर्पित किए जाने के उपरान्त भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मेरे द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा तो संबंधी कार्यवाह लिपिक के द्वारा बताया गया कि उनके पास योगदान संबंधी कोई आवेदन अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है साथ ही उनके द्वारा ही यह बताया गया कि पूर्व में समर्पित योगदान की छायाप्रति निबंधित डाक से पुनः भेज दे जिसे कोई नहीं फाड़ सकता है, तत्पश्चात् मेरे द्वारा दिनांक-27.06.2023 को निबंधित डाक से पूर्व में समर्पित योगदान आवेदन की छायाप्रति अंचलाधिकारी महोदय, सदर को भेज दिया।

10. कि अंचल कार्यालय द्वारा जो भी पत्राचार मुझ से किया गया है वह माह जून, 2013 एवं जुलाई, 2013 में किया गया है, इसके अतिरिक्त किसी भी स्तर पर मेरे विरुद्ध कोई पत्राचार नहीं किया गया है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मेरे पत्नी के द्वारा मेरे अस्वस्थता के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के आलोक में कोई पत्राचार नहीं किया गया।

11. कि यदि मैं लम्बे अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित था तो कार्यालय द्वारा मुझे निलंबित भी नहीं किया गया और न ही वर्ष-2019 में मेरे विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर कोई कार्रवाई की गई, बल्कि मेरे द्वारा कार्यालय में योगदान स्वीकृत करने का दबाव बनाए जाने पर वर्ष 2023 में पुनः आरोप पत्र गठित किया गया, जिसपर प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

12. कि यदि मैं लम्बे अवधि तक अनाधिकृत अनुपस्थित था तो कार्यालय को इसकी सूचना समय-समय पर मुझे निबंधित डाक से भेजनी चाहिए थी तथा अंतिम अवसर के रूप में इसकी सूचना पेपर प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित करनी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि कार्यालय को जानकारी थी कि मैं चिकित्सार्त् हूँ तथा स्वस्थ होने के उपरान्त कार्यालय में योगदान समर्पित किया है, जिस कारण कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार मुझ से नहीं किया गया।

13. कि संदर्भित मामले में आजतक कार्यालय द्वारा मुझे निलंबित नहीं किया गया है, यदि मैं 10 वर्षों से कार्यालय से अनुपस्थित हूँ तो कार्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के उपरान्त मुझे निलंबित कर देना चाहिए था, परन्तु अद्यतन मुझे निलंबित नहीं किया गया है।

स्पष्टतः मैं लगभग 10 वर्ष तक कार्यालय से अनुपस्थित नहीं था, बल्कि मैं स्वयं की अस्वस्थता एवं पारिवारिक कारणों से स्वास्थ्य लाभ हेतु लगभग 03-04 वर्षों के लिए घर से अन्यत्र चला गया था, जिसकी सूचना मेरी पत्नी के द्वारा तत्कालीन अंचलाधिकारी महोदय, सदर को पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से जुलाई, 2013 में भिजवा दी थी तथा योगदान समर्पित किए जाने के उपरान्त कार्यालय के टाल-मटोल करने के कारण योगदान समर्पित नहीं होने एवं कोविड प्रोटोकॉल के प्रभावी हो जाने के कारण अतिरिक्त समय व्यतीत हुआ है, इसलिए उक्त अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र को मेरे द्वारा प्राप्त नहीं करने का प्रश्न है तो इस संबंध में भवदीय को स्पष्ट करना है कि मैं उक्त अवधि में स्वास्थ्य लाभ एवं चिकित्सा हेतु अन्यत्र चला गया था, जिस कारण उक्त पत्र को मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

भवदीय निदेश पर संचालित विभागीय कार्यवाही में मैंने उपस्थित होकर सभी तथ्य/साक्ष्य संचालन पदाधिकारी महोदय को समर्पित किया, परन्तु संचालन पदाधिकारी महोदय ने मेरे द्वारा समर्पित तथ्यों पर बिना कोई विचार किए ही सामान्य अनुक्रम में उपस्थापन पदाधिकारी के तथ्यों को ही अपने शब्दों में अभिलेखित करते हुए बिना किसी विवेचना के ही प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित मान लिया गया है तथा बहादुरपुर थाना काण्ड सं०-75/2013 में आरोपित होने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम-76 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई, जबकि बहादुरपुर थाना काण्ड सं०-75/2013 से न तो मेरा कोई सरोकार है औ न ही मैं उक्त काण्ड में अभ्युक्त हूँ।

प्रस्तुत मामले में उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा जो तथ्य संचालन पदाधिकारी महोदय को उपलब्ध कराया गया है उससे स्पष्ट होता है कि उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा विशेष अभिरुची लेते हुए तथ्यों से पृथक जाकर मेरे विरुद्ध अपुष्ट जानकारी इकट्ठा कर संचालन पदाधिकारी महोदय को प्रतिवेदित किया है, जबकि उपस्थापन पदाधिकारी का दायित्व आरोपित कर्मों के द्वारा मांग किए जाने वाले तथ्यों को उपलब्ध कराना है न कि प्रतिवेदित आरोपों से पृथक जाकर भ्रामक प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को समर्पित कर संचालन पदाधिकारी को दिग्भ्रमित करना है।

प्रस्तुत मामले में कतिपय अवधि के लिए कार्यालय से अनुपस्थित रहना जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि परिस्थितिजन कारणों के कारण ऐसा हुआ है। भवदीय को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे द्वारा कोई लापरवाही अथवा स्वेच्छाचारिता बरती गई है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तथा भवदीय को विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी।

अतः भवदीय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करते हुए पदस्थापित कार्यालय में योगदान स्वीकृत करने तथा अवकाश पर बिताई गई अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु अंचलाधिकारी महोदय, सदर दरभंगा को निदेशित करने की कृपा की जाय। इस असीम कृपा हेतु मैं भवदीय का सदा आभारी रहूँगा।”

उक्त द्वितीय कारणपृच्छा में प्रतिवेदित आरोप के संबंध में आरोपी कर्मों द्वारा अपने बचाव में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया, जिससे संचालन पदाधिकारी द्वारा संचालन प्रतिवेदन में सही पाये गये आरोप को खंडित किया जा सके। वर्णित करना है कि, बिहार सेवा संहिता के नियम-76 में अंकित है कि “जबतक कि किसी मामले की खास परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार अन्यथा निर्धारित न करें, सरकारी सेवक, भारत में बाह्य-सेवा को छोड़कर अन्यत्र छुट्टी के साथ या बिना छुट्टी के, कर्तव्य से पाँच वर्ष तक लगातार अनुपस्थिति के बाद, सरकारी – नियोजन में नहीं रह जाता है (क) किसी भी सरकारी सेवक को पाँच वर्ष से अधिक के लिए किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी।

—:निर्णयज विधि:—

[पाँच वर्ष या अधिक की अनुपस्थिति के आधार पर सरकारी सेवक की सेवा की स्वतः समाप्ति का प्रावधान अवैध है—विभागीय कार्यवाही आवश्यक है। रामानन्द सिंह बनाम बिहार सरकार, 1991 (2) पी०एल०जे०आर० 198 ।

विभागीय कार्यवाही किये बिना सेवा की स्वतः समाप्ति नहीं हो सकती। मो० सलीम बनाम बिहार सरकार, 1999 (1) पी०एल०जे०आर० 229]। “

अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-V नियम-14 के कंडिका-xi में निहित प्रावधानानुसार मैं राजीव रौशन, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी –सह–समाहर्ता, दरभंगा मो० शाहनवाज अली शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी, अंचल कार्यालय, सदर दरभंगा को आदेश निर्गमन की तिथि से “सेवा से बर्खास्तगी” (जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरहता होगी) का दण्ड अधिरोपित करता हूँ।

इस आशय की प्रविष्टि मो० शाहनवाज अली शाह के सेवापुस्त में लाल स्याही से अंकित की जायेगी। साथ ही विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

मो० शाहनवाज अली शाह, निलंबित कार्यालय परिचारी, अंचल कार्यालय, सदर दरभंगा से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) नाम	:-	मो० शाहनवाज अली शाह
(2) पिता	:-	स्व० अब्दुल जब्बार
(3) पदनाम	:-	कार्यालय परिचारी
(4) जन्मतिथि	:-	29.11.1984
(5) नियुक्ति की तिथि	:-	29.04.2006
(6) वेतनमान	:-	5200-20200 ग्रेड पे-1800
(7) स्थायी पता	:-	ग्राम- पुरखोपट्टी, पो०-लहेरियासराय, प्रखण्ड+ थाना- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट, जिला दण्डाधिकारी –सह–समाहर्ता, दरभंगा।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2025

सं० 15/एम 1-06/2017-225—बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत दीघा घाट, पटना में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा घाट, पटना की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय जेवियर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, दीघा घाट, पटना से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन मूल्यांकन / समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत जेवियर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, दीघा घाट, पटना को बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा घाट, पटना के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा घाट, पटना के नाम से निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं समान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अमित कुमार पुष्पक, उप-सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचनाएं

20 जनवरी 2025

सं० 1/प्रो.1-01/2023-100—श्री सुधीर कुमार यादव, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त गया संग्रहालय, गया, नारद संग्रहालय, नवादा एवं बिहारशरीफ संग्रहालय, बिहारशरीफ का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. प्रस्ताव पर माननीय (उप मुख्य) मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

स्मिता कुमारी, अवर सचिव।

18 दिसम्बर 2024

सं० 1/प्रो.1-01/2023/243—श्री सुधीर कुमार यादव, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त बेगूसराय संग्रहालय, बेगूसराय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय (उप मुख्य) मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

सुशान्त कुमार, अवर सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

प्रभार रिपोर्ट

1 जनवरी 2025

सं० 02—अधोहस्ताक्षरी मैं, सीमा त्रिपाठी, भा०प्र०से० (बी.एच.2009), विशेष सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार पटना ने आज दिनांक 01.01.2025 के पूर्वो० में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या—20047 दिनांक—13.12.2024 एवं अधिसूचना संख्या—30 दिनांक 01.01.2025 के आलोक में सचिव स्तर का (अधिसमय वेतनमान में) प्रभार स्वतः ग्रहण किया।

(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या—20047 दिनांक—13.12.2024 एवं अधिसूचना संख्या—30 दिनांक 01.01.2025 द्रष्टव्य)।

(सीमा त्रिपाठी)

भारग्रही पदाधिकारी।

आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अवर सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचनाएं

9 दिसम्बर 2024

सं० 1/प्रति. 5—01/2019/230—श्रीमती रचना पाटिल, भा०प्र०से०, निदेशक, संग्रहालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यहित में अगले आदेश तक के लिए निदेशक, पुरातत्व, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद का प्रभार सौंपा जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय (उप मुख्य) मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार, अवर सचिव।

20 दिसम्बर 2024

सं०1/नियु.1—01/2019/1960—श्री फहद सिद्दिकी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सहायक सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना के प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें सांस्कृतिक कार्य निदेशालय (मुख्यालय) में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. सुश्री कीर्ति आलोक, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

3. पूर्व के आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुशांत कुमार, अवर सचिव।

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं (संशोधित)

10 जनवरी 2025

सं० कौन/भी—144/2023—20/सी०—श्री बलराम प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, वसूली कोषांग, पूर्णियाँ के द्वारा दिनांक—23.12.2023 को सिवान अंचल में बिना पूर्वानुमति के वाहन निरीक्षण कार्य करने एवं निरीक्षण के उपरान्त वाहन संख्या—BR01GF-5411 पर लदे माल के विरुद्ध परिवहन के समय वांछित कागजात नहीं होने के बावजूद बिना किसी कार्रवाई के वाहन को छोड़ देने के उनके कृत्य को

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-68, धारा-129 एवं नियम-138(बी) का उल्लंघन तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-390 दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग- IV के नियम-9(i)(क) के तहत निलंबित किया गया।

निलंबन के उपरांत उक्त आरोप के लिए उनसे विभागीय पत्रांक-69/सी दिनांक- 13.03.2024 द्वारा बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत इसे स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-230/सी दिनांक- 26.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री बलराम प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान (निलंबित) को अधिसूचना ज्ञापांक-232/सी दिनांक-26.07.2024 द्वारा निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री बलराम प्रसाद, राज्य कर उपायुक्त के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए श्री बलराम प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, वसूली कोषांग, पूर्णियाँ को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री बलराम प्रसाद, तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर उपायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, वसूली कोषांग, पूर्णियाँ को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक-230/सी दिनांक-26.07.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

10 जनवरी 2025

सं० कौन/भी-144/2023-21/सी०—श्री अरुण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल(अंकेक्षण), भागलपुर के द्वारा दिनांक-23.12.2023 को सिवान अंचल में बिना पूर्वानुमति के वाहन निरीक्षण कार्य करने एवं निरीक्षण के उपरांत वाहन संख्या-BR01GF-5411 पर लदे माल के विरुद्ध परिवहन के समय वांछित कागजात नहीं होने के बावजूद बिना किसी कार्रवाई के वाहन को छोड़ देने के उनके कृत्य को बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-68, धारा-129 एवं नियम-138(बी) का उल्लंघन तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-391 दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-IV के नियम-9(i)(क) के तहत निलंबित किया गया।

निलंबन के उपरांत उक्त आरोप के लिए उनसे विभागीय पत्रांक-68/सी दिनांक- 13.03.2024 द्वारा बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री नाथ से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत इसे स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-231/सी दिनांक- 26.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री अरुण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान (निलंबित) को अधिसूचना ज्ञापांक-233/सी दिनांक-26.07.2024 द्वारा निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री अरुण नाथ, राज्य कर सहायक आयुक्त के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए श्री अरुण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल(अंकेक्षण), भागलपुर को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरुण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल(अंकेक्षण), भागलपुर को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक-231/सी दिनांक- 26.07.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

27 दिसम्बर 2024

सं० कौन/भी-111/2007-432/जी—डॉ० बी० के० मिश्रा, सचिव, प्रज्ञा भारती (एन०जी०ओ०), शिवगंज, आरा द्वारा निगरानी विभाग, बिहार, पटना को परिवाद पत्र दिया गया। जिसके आलोक में निगरानी विभाग के गठित धावादल द्वारा श्री अनिल कुमार, तत्कालीन वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल, आरा को दिनांक-31.03.2007 को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया एवं इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-044/2007 दिनांक-31.03.2007 दर्ज किया गया।

उक्त आरोप में श्री अनिल कुमार को विभागीय अधिसूचना सं०-165 दिनांक-18.04.2007 द्वारा दिनांक-31.03.2007 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया।

निगरानी विभाग द्वारा अभियोजन की स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विधि विभाग से अभियोजन की मांग की गयी। विधि विभाग द्वारा आदेश सं०-एस०पी०/नि०/25/2007/2988/जे० दिनांक-02.07.2007 के माध्यम से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात् आरोप पत्र गठित करते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानानुसार द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया एवं प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-197/सी दिनांक-28.05.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही श्री कुमार दिनांक-31.01.2014 को सेवानिवृत्त हो गये। इसके कारण श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अधिसूचना संख्या-35/सी दिनांक-21.02.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) में सम्मरिवर्तित किया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री कुमार के सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध गठित तीन आरोपों में से दो आरोप यथा आरोप सं०-1 (रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने से संबंधित) एवं आरोप संख्या-2 (उचित शास्ति अधिरोपित नहीं करने एवं अधिरोपित शास्ति को सरकारी खजाने में जमा नहीं करने से संबंधित) को संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः प्रमाणित बताया गया।

संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये श्री कुमार से पत्रांक-194/सी दिनांक-24.09.2015 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण में पूर्व के स्पष्टीकरण से भिन्न कोई दूसरा तथ्य नहीं पाया गया जिसके कारण श्री कुमार के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुये पूर्ण पेंशन की राशि, देय उपादान की राशि, अव्यवहृत अवकाश नकदीकरण की राशि आदि को रोके जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सक्षम प्राधिकार से प्राप्त आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं०-250/सी दिनांक-22.07.2016 द्वारा श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त को निम्नांकित दंड संसूचित किया गया :-

- (i) सेवानिवृत्ति के पश्चात् भुगतये पेंशन राशि को पूर्ण रूप से रोका जाता है।
- (ii) देय उपादान की राशि को पूर्ण रूप से रोका जाता है।
- (iii) सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अव्यवहृत अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति को पूर्ण रूप से रोका जाता है।
- (iv) निलंबन अवधि का विनियमन के लिए निलंबन अवधि दिनांक-31.03.07 से दिनांक-31.07.2011 तक में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

ध्यातव्य है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री अनिल कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी से कतिपय कागजातों की मांग की गयी। मांगे गये कागजात निगरानी विभाग से संबंधित होने के कारण इनकी मांग विभागीय पत्रांक-45/सी दिनांक-02.02.2010 के द्वारा निगरानी विभाग से की गयी। कई स्मार के बाद निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि श्री अनिल कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में ब्यूरो वही कागजात इन्हें उपलब्ध करायेगी जिस बिन्दुओं पर इनके विरुद्ध आरोप का गठन किया गया है। इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं०-27/08 में इनके द्वारा मांगे गये कागजात इनके विरुद्ध दर्ज अपराधिक कांड से संबंधित है, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, अतः ब्यूरो द्वारा इन्हें प्रदान करना संभव नहीं है। निगरानी विभाग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध विशेष न्यायालय, निगरानी में भी धारा 207 Cr.P.C. के अन्तर्गत कागजात दिनांक-14.12.2007 को प्रदान करने हेतु ब्यूरो द्वारा भेजे जा चुके हैं जहां उपस्थित होकर उन्हें उक्त कागजात प्राप्त करने थे। ज्ञातव्य है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध चलने वाली विभागीय कार्यवाही न्यायिक वाद से पृथक् प्रक्रिया है। अतः न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना ब्यूरो के लिए सम्भव नहीं है। उक्त आशय की सूचना श्री अनिल कुमार को विभागीय पत्रांक-181/सी दिनांक-08.07.2010 द्वारा दे दी गयी।

उल्लेखनीय है कि वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराने के बिन्दु को आधार बनाते हुए श्री अनिल कुमार के द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-250/सी दिनांक-22.07.2016 के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-19030/2016 दायर किया गया।

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-19030/2016 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-28.02.2019 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में (1) विभागीय अधिसूचना संख्या-250/सी दिनांक-22.07.2016 द्वारा दिये गये दण्ड को अधिसूचना संख्या-166/सी दिनांक-07.06.2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया। (2) विभागीय पत्रांक-1837 दिनांक-27.06.2019 द्वारा Current Pension चालू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं वस्तुस्थिति से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग को अवगत कराते हुए वांछित सभी कागजातों/अभिलेखों की मांग विभागीय पत्रांक-120/सी (अनु0) दिनांक-03.04.2019 द्वारा की गयी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग से वांछित कागजात प्राप्त होते ही श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए उनके विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-224/सी दिनांक-05.08.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-4671/2022 दायर किया गया जिसमें दिनांक-06.08.2024 को न्याय निर्णय पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

- Learned Advocate on behalf of the respondents, on the other hand, refers to the statement made by him in paragraphs 5, 6, 7 and 8 of the original counter affidavit wherein it is submitted on behalf of the respondents that initially, the respondents filed counter affidavit on 18th July, 2022 but it was misplaced from the office of the Standing Counsel 11 and with the permission of the Court, by way of a supplementary counter affidavit, the original counter affidavit has been filed. I have perused the entire counter affidavit as well as the supplementary affidavit. Before initiation of the departmental proceeding under Rule 43(b), the disciplinary authority did not consider the proviso to Rule 43(b), no government's sanction was obtained before initiation of disciplinary proceeding. The proceeding under Rule 43(b) was initiated after a lapse of about twelve years of the alleged incident, no witness was cited to prove the departmental charge and the departmental proceeding was being continued by the respondents only to assure that the delinquent officer may not get his retiral benefits.
- In view of the above discussion and the finding of the Hon'ble Supreme Court as well as this Court by the Division Bench, Full Bench and the present Bench, there is no other alternative but to quash the departmental proceeding initiated de novo against the petitioner on 14th June, 2019.
- Accordingly, the departmental proceeding against the petitioner is quashed and set aside.
- The petitioner is entitled to get all pensionary benefits and consequential reliefs.
- The respondents are directed to release the same within forty-five days from the date of this order.
- However, there shall be no order as to costs.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन हेतु विचार के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने एवं निगरानी थाना कांड 44/2007 लंबित है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले में एल0पी0ए0 दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एल0पी0ए0 दायर किये जाने के बिन्दु पर असहमति व्यक्त की गयी। फलस्वरूप श्री कुमार के सेवान्त लाभों के भुगतान के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-1093 दिनांक-20.11.2018 के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ मामले को प्रस्तुत किया गया।

दिनांक-27.11.2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत प्रस्तुत मामले को पूर्वादाहरण नहीं मानने की शर्त पर श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने एवं तदनुसार परिणामी लाभ प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गयी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प ज्ञापांक-224/सी दिनांक-05.08.2019 को निरस्त किया जाता है एवं उनके सेवान्त लाभों के भुगतान का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

27 दिसम्बर 2024

सं० कौन/भी(न्या०)-902/2019-433/सी०—श्री पवन कुमार दिनांक-30.11.2015 को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त के पद से वार्द्धक्य सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के समय उनके विरुद्ध बेगुसराय अंचल के पदस्थापन काल में ट्रेप केस से संबंधित बेगुसराय नगर काण्ड संख्या-125/85 दिनांक-25.05.1985 में धारा-120(बी), 409, 467, 468, 471 भा०द०वि० 5(2), 5(1) (सी०)(डी०) पीसी दर्ज होने के कारण उनके पक्ष में विभागीय पत्रांक-6904(अनु०) दिनांक-14.12.2015 द्वारा उपादान की राशि को रोकते हुए 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2- पुनः Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs) Government of India के पत्रांक-4/CFB/2016(14)-VII-2539 दिनांक-22.07.2016 के माध्यम से इस आशय की सूचना प्राप्त हुयी कि श्री पवन कुमार द्वारा अपने सेवाकाल में कुल-09 विदेश यात्राएँ की गयी। बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्राओं के प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके सेवाकाल को असंतोषप्रद होने के आधार पर विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-6061 दिनांक-28.11.2018 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :-

“श्री पवन कुमार, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को पूर्व में निर्धारित 90(नब्बे) प्रतिशत औपबंधिक पेंशन से 25 प्रतिशत की कटौती 5(पाँच) वर्षों के लिए किया जाता है।”

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री पवन कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-2400/2019 पवन कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

मामले पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-2400/2019 पवन कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-19.11.2024 को न्याय निर्णय पारित किया गया है, जिसका क्रियाशील अंश निम्नवत् है :-

27. In view of the discussion made, hereinabove, as also in absence of any Rules, Regulation and the instructions to support the impugned order of punishment, this Court has no hesitation to hold it unsustainable and thus the notification dated 28.11.2018, contained in Memo No. 6061 is hereby set aside. The concerned respondent is hereby directed to ensure the payment of all the admissible amount of gratuity, leave encashment as well as remaining 10% of pension and arrears thereof preferably within a period of twelve weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

28. The writ petition stands allowed. There shall be no order as to costs.

पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री पवन कुमार, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त के मामले पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-6061 दिनांक-28.11.2018 द्वारा संसूचित दण्ड को निरस्त करते हुए उनके पूर्व के लंबित सेवान्त लाभों एवं बकाया के भुगतान का निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

28 दिसम्बर 2024

सं० 6/नि०प्रति०नियु०-01-04/2024-5659/वा०कर-67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित बिहार वित्त सेवा के अन्तर्गत राज्य-कर सहायक आयुक्त के पद पर विभागीय अधिसूचना संख्या-655 दिनांक-07.02.2024 के आलोक में औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उनके नाम के सामने कॉलम-6 में अंकित वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना में दिये गये योगदान की तिथि से पुनरीक्षित वेतन स्तर-9 (रु०-53100-167800) में बिहार वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत राज्य-कर सहायक आयुक्त (परीक्ष्यमान) के पद पर योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-7 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	उम्मीदवार का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	गृह जिला	योगदान की तिथि	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7
1	मो० सोहेब जमाँ	69	अनारक्षित	पटना	17.12.2024 (पूर्वा०)	औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद
2	पूर्णिमा कुमारी साव	73	अनारक्षित	सिवान	13.12.2024 (पूर्वा०)	जहानाबाद अंचल, जहानाबाद

2. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के तत्काल प्रभाव से अपना योगदान नवपदस्थापित कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे।

3. नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 01.01.2025 से प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के निमित्त बिपार्ड कुशडिहरा, गया में योगदान देने हेतु दिनांक 30.12.2024 अपराह्न के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। वे दिनांक 31.12.2024 को अपराह्न 4:00 बजे तक निश्चित रूप से बिपार्ड, गया परिसर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

30 दिसम्बर 2024

सं० 6/मु०क०-35-07/2008-5665/(वा०कर)-माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-14138/2008 इकबाल अहमद जमशेद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 09.01.2024 को पारित न्यायनिर्णय के अनुपालन में विहित प्रक्रिया के तहत श्री इकबाल अहमद जमशेद, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर उपायुक्त को इनसे ठीक कनीय पदाधिकारी श्री कृष्णा नन्द सिन्हा, तत्कालीन वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त के योगदान की तिथि 21.06.2007 से वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान- 12,000-16,500 रु०) से वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान रु०-14,300-18,300 रु०) कोटि के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

2. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

21 जनवरी 2025

सं० 21/पि०व०रा०आ०-01/2012, सा०प्र० 1198—पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम 1993 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-9 में यथाविनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु माननीय

न्यायमूर्ति (से.नि.), श्री संजय कुमार को अगले तीन वर्षों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

2. यह आदेश पदभार-ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद, अपर सचिव ।

लघु जल संसाधन विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

27 दिसम्बर 2024

सं० 6595—अद्योहस्ताक्षरी मैं, धनंजय कुमार, बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सिविल लिस्ट-2024, वरीयता क्रमांक-71), आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना आज दिनांक-24.12.2024 के पूर्वाह्न में प्रधान आप्त सचिव के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ।

(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-09/प्रो-02-01/2023, सां०प्र-20542 दिनांक-24.12.2024 कृपया द्रष्टव्य)।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह० अस्पष्ट, सचिव ।

(धनंजय कुमार)
भारग्राही पदाधिकारी

आदेश से,
संजीव कुमार अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 62—I, Anita Mishra W/o Late Navin Kumar Mishra R/o 3/237, Ramayatan New Patliputra, New Patliputra Boring Road, Patna-800013, Bihar declare vide affidavit No. 11 dated 06/12/2024 that I shall be known as Anita Mishra instead of Anita Navinkumar Mishra. That I shall be known as Anita Mishra for all purposes.

Anita Mishra.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० वा०सं०नि० (स्था०)-01-69/2024-1347

वायुयान संगठन निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
हवाई अड्डा, पटना- 800014

संकल्प
17 जनवरी 2025

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि कैप्टन विवेक परिमल, विमान चालक-सह-उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की "प्रगति यात्रा" के क्रम में निदेशालय में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं, जिससे इनके द्वारा जिलों से हेलिपैड की NOC, Co-ordinates, फोटो तथा विडियो को हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गयी है।

2. कै० विवेक परिमल दिनांक 03.01.2025 से लगातार अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं तथा अपने दोनों मोबाईल नम्बर भी बन्द करके रखे हुये हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री की "प्रगति यात्रा" के क्रम में जिलों से हेलिपैड की NOC, Co-ordinates, फोटो तथा विडियो को हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का वहन उन्हें निदेशालय का उत्तरदायी प्रबंधक होने के नाते करना था।

3. साथ ही कै० विवेक परिमल द्वारा वायुयान संगठन निदेशालय में विमान चालक के पद पर पदस्थापित रहते हुए राज्य के अतिविशिष्ट व्यक्तियों यथा महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य के वायुमार्ग से गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले राजकीय विमान King Air C-90 A/B, VT-EBG के परिचालन हेतु आवश्यक Currency प्राप्त नहीं किया गया। जिसके कारण राजकीय विमान के परिचालन हेतु वाह्य स्रोत से अतिरिक्त व्यय पर Co-Pilot भर्तगाना पड़ा है।

4. उपरोक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1) के तहत कै० विवेक परिमल विमान चालक-सह-उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबनावस्था में इनका मुख्यालय उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

5. कै० परिमल के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्यवाई की जायेगी।

6. कै० परिमल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत निलंबनावस्था में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. उपरोक्त पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे, निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>